Useful For Prelims

Date: 26 December 2025

लखनऊ में गुरुवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी, दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विशालकाय प्रतिमाओं का दृश्य ● एएनआइ

अटलजी को समर्पित देश के पहले संग्रहालय का लोकार्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर : पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित देश के पहले संग्रहालय का ग्वालियर में गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। महाराज बाड़ा स्थित जिस गोरखी स्कूल में अटलजी पढ़े थे, वहीं इस म्यूजियम को तैयार किया गया है। इस संग्रहालय में अटलजी की यादों को संजोकर रखा गया है। म्यूजियम में 10 गैलरियां हैं, जिनमें अटलजी का पूरा जीवन नजर आता है। इनमें अटलजी के पारिवारिक चित्र, अटल यात्रा गैलरी में उनकी जीवन गाथा यानी पढ़ाई-लिखाई से लेकर राजनीति तक का सफर, डार्करूम में विश्व की प्रसिद्ध हस्तियों के साथ अटलजी के फोटो का संग्रह, आर्टिफेक्ट गैलरी में अटलजी का व्यक्तिगत सामान जैसे तौलिया, ट्रिमर, कप-प्लेट, कुर्सी, सफारी सूट, कुर्ते आदि रखे गए हैं। सारा सादा सामान अटलजी के सरल व्यक्तित्व को दर्शाता है।

Dainik Jagaran Page No-13

दलों और विचारधारा से परे राजनीतिकों ने अटल को याद किया | 101वीं जयंती | पूर्व प्रधानमंत्री की राजनीतिक यात्रा विकास की भावना का प्रतिबिंब

वाजपेयी के प्रतिद्वंद्वी भी मानते हैं उन्हें भारतीय राजनीति का अजातशत्रु

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

लखनऊ लोकसभा सीट से पांच बार सांसद रहे पूर्व प्रधानमंत्री और 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति का 'अजातशत्रु' कहा जाता था, जिनके कोई शत्रु नहीं थे और यह बात उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके राजनीतिक विरोधी भी स्वीकार करते हैं।

वाजपेयी 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लखनऊ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इनमें उनके तीन प्रधानमंत्री कार्यकाल भी शामिल हैं। उनकी 101वीं जयंती पर उनके कई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, खासकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वालों ने भी उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया।

वाजपेयी के खिलाफ 1996 में में चुनाव लड़ चुके अभिनेता से नेता बने राज बब्बर ने स्वीकार किया कि उन्हें शुरुआत से ही यह मुकाबला औपचारिकता जैसा लगा। उन्होंने कहा, 'जिस पल समाजवादी पार्टी ने मुझे लखनऊ से अटल जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया, मुझे लगा कि नतीजा पहले से तय है।'

बब्बर ने कहा कि जिनके भाषण सुनकर वे बड़े हुए, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का विचार ही मन घबराहट पैदा करने वाला था। उन्होंने याद किया, 'दसवीं कक्षा के छात्र के रूप में हम उनके भाषण सुनने और समझने के लिए आगरा के सूरजभान का फाटक जाते थे।' उन्होंने कहा कि अटल जी के भाषणों ने उन्हें स्कूल और कालेज की बहसों की तैयारी में मदद की।नामांकन के बाद का एक किस्सा सुनाते हुए बब्बर ने बताया, 'मुंबई जाने वाली उड़ान में मैं उनके सामने वाली सीट पर था। मैंने उनके पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। मैंने कहा कि अगर मेरे मुंह से गलती से भी उनके खिलाफ कुछ निकल गया, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।

अटल जी मुस्कुराए और बोले कि उन्हें भरोसा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा।' उन्होंने कहा कि अटल जी से उन्होंने सीखा कि राजनीतिक विरोधी दुश्मन नहीं होते। बब्बर ने कहा, '1996 के बाद जब मुझे फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो मैंने साफ मना कर दिया। बाद में जब वह प्रधानमंत्री और मैं राज्यसभा सदस्य बना तो उन्होंने 1996 के चुनाव में मेरे व्यवहार की सराहना की।'

लखनऊ के प्रेरणा स्थल में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा।

पूर्व महापौर दाऊजी गुप्ता ने 1998 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। गुप्ता के पुत्र रत्नेश गुप्ता ने बताया कि 1998 के चुनाव प्रचार के दौरान जब दोनों नेताओं के काफिले आमने-सामने आए, तो उनके पिता ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले अटल जी के काफिले को जाने दिया जाए। उन्होंने कहा, 'अटल जी ने अपनी खास मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर जवाब दिया। बाद में मिलने पर उन्होंने मजाक में कहा-सियासत में रास्ता छोड़ना ठीक नहीं, तो मेरे पिता ने कहा-दूसरों का रास्ता रोकना भी ठीक नहीं। और दोनों हंस पड़े।'

उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद दिनेश शर्मा ने वाजपेयी की सादगी को याद करते हुए कहा, 'एक बार वह हमारे घर आए थे। मैं इतना घबरा गया कि उनके कपड़ों पर थोड़ी खीर गिर गई, लेकिन अटल जी बस मुस्कुराए और मुझे सहज कर दिया।' उन्होंने कहा कि वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा आधुनिक भारत के विकास की भावना को दर्शाती है।

Jansatta Page No-1

भारत सरकार

भारत की बाल शक्ति @2047

आइये एक साथ मिलकर मनाएं साहिबज़ादों की वीरता एवं साहस से प्रेरित

वीर बाल दिवस

26 दिसंबर 2025

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा

देश भर के बच्चों को संबोधन

एवं

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बच्चों से संवाद

CBC 46101/13/0020/2526

डायर को मार उधम सिंह ने लिया जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला

उधम सिंह का जन्म 1899 में आज ही पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में हजारों लोग रौलेट एक्ट के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर ने रेजिनाल्ड की कार्रवाई का समर्थन किया था। 13 मार्च, 1940 को लंदन में माइकल डायर को गोली मार कर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया। 31 जुलाई, 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई।

Dainik Jagaran Page No-14

मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की

1898 में आज ही पोलिश-फ्रांसीसी विज्ञानी मैरी क्यूरी ने पिचब्लेंडे नामक एक सामान्य यूरेनियम अयस्क पर प्रयोग करते हुए रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। उन्होंने पाया कि यह अयस्क परिष्कृत यूरेनियम से अधिक रेडियोधर्मी था। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल मिला।

Dainik Jagaran Page No-14

पहली बार अमेरिका में की गई पेट की सफल सर्जरी

1809 में आज ही अमेरिकी चिकित्सक एफ्रैम मैकडावेलजेन ने जेन टाड क्राफर्ड के अंडाशय से 10 किग्रा का एक विशाल ट्यूमर निकाला था। उन्हें ओवेरियोटामी और पेट की सर्जरी का जनक माना जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट लगे और इसे बिना किसी एनेस्थीसिया के किया गया।

Dainik Jagaran Page No-14

संयुक्त राष्ट्र मना रहा 80वीं वर्षगांठ | विश्लेषण | आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अग्रणी भूमिका निभाना जारी रखेगा

वैश्विक संकटों के बीच भारत बड़ी भूमिका निभाने को तैयार

संयुक्त राष्ट्र, 25 दिसंबर (भाषा)।

दुनिया के कई इलाकों में जारी संघर्षों, वित्तीय संकट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना के बीच, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई, जबकि भारत ने विश्व निकाय से 'नेतृत्व और आशा' पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और एक बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की।

यूक्रेन और गाजा में संघर्ष, सूडान से लेकर म्यांमा तक दुनिया भर के कई अन्य हिस्सों में युद्ध की स्थिति ने 2025 में भी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र और उसकी शक्तिशाली, लेकिन ध्रुवीकृत, सुरक्षा परिषद की अक्षमता को उजागर किया। जैसे-जैसे राष्ट्र मानवीय आपात स्थितियों, जलवायु संकट और आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं, वैसे-वैसे संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल और मुखरता से उठाए जा रहे हैं जिनमें प्रमुख सवाल यह है कि क्या 1945 में स्थापित 80 साल पुराने इस संगठन के पास 21वीं सदी में अस्थिर दुनिया की समस्याओं का समाधान है।

इस पृष्ठभूमि में, भारत ने इस बहुपक्षीय संगठन में सुधार के लिए जोरदार आह्वान किया है। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि एक 'निष्पक्ष रपट कार्ड' से पता चलेगा कि संयुक्त राष्ट्र संकट की स्थिति में है। जब संघर्षों से शांति खतरे में पड़ती है, जब संसाधनों की कमी से विकास पटरी से उतर जाता है, जब आतंकवाद से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तब संयुक्त राष्ट्र गतिरोध में फंसा रहता है। आम सहमति बनाने की क्षमता कम होने के साथ-साथ इसके प्रति विश्वास भी घटता जाता है।'

भारत ने दुनिया को बताया कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता में कमी का मुख्य कारण सुधारों का प्रतिरोध रहा है, और नई दिल्ली विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अधिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार है, जो अपने वर्तमान 15 सदस्यों के साथ 2025 की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जयशंकर ने कहा, 'परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए। एक सुधार किए गए परिषद को सही मायने में प्रतिनिधि होना चाहिए। भारत अधिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार है।' संयुक्त राष्ट्र का नौवां दशक नेतृत्व और आशा का दशक होना चाहिए। भारत अपनी पूरी भूमिका निभाएगा, और उससे भी अधिक करेगा।'

जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अग्रणी भूमिका निभाना जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग विश्व निकाय के सर्वोच्च स्तर से भी उठी, जब महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लिए पुरजोर तरीके से आह्वान किया ताकि इसे अधिक प्रतिनिधित्व युक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।

जयशंकर ने कहा, 'परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए। एक सुधार किए गए परिषद को सही मायने में प्रतिनिधि होना चाहिए। भारत अधिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार है।'

ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र से रिश्ते सौहार्दपूर्ण नहीं रहे

ट्रंप के अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी संयुक्त राष्ट्र से रिश्ते बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रहे और उस समय उन्होंने इस विश्व निकाय को 'लोगों के एक साथ आने, बात करने और अच्छा समय बिताने के लिए सिर्फ एक क्लब' के रूप में वर्णित किया था। दूसरे कार्यकाल में उनकी संयुक्त राष्ट्र के प्रति तल्खी और बढ़ गई।

Jansatta Page No-13

व्यापार वार्ता को लेकर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा

भारत पारस्परिक लाभकारी व संतुलित करार का पक्षधर

न्यूयार्क/वाशिंगटन, 25 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी और संतुलित व्यापार समझौता करने के लिए अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। क्वात्रा ने एक साक्षात्कार में कहा, 'व्यापार एवं शुल्क के मुद्दे पर... हम जल्द पारस्परिक रूप से लाभकारी और संतुलित व्यापार समझौता करने की उम्मीद में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसआर) के साथ लगातार संपर्क में हैं।'

उन्होंने कहा, 'इस पूरे वर्ष हमारा यही निरंतर प्रयास रहा है। फरवरी की शुरुआत में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ही संबंधों की नींव रखी गई थी। हमने कई क्षेत्रों में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और ठोस परिणाम पर सहमति व्यक्त की। अंतरिक्ष भी उनमें से एक है।' क्वात्रा ने बुधवार को भारत द्वारा अमेरिकी संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण को भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण एवं बड़ा दिन करार दिया।

मालूम है कि एक ऐतिहासिक मिशन के तहत इसरो के सबसे भारी प्रक्षेपण यान 'एलवीएम-3 एम6' ने एक अमेरिकी संचार उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में बुधवार को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया जिसे अंतरिक्ष एजंसी प्रमुख ने देश के लिए तोहफा करार दिया। प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 एम6 ने 6,100 किलोग्राम वजनी 'ब्लूबर्ड ब्लाक-2' उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। 'ब्लूबर्ड ब्लाक-2' मिशन का उद्देश्य उपग्रह के जरिए सीधे मोबाइल संपर्क उपलब्ध कराना है। यह नेटवर्क कहीं भी, कभी भी, सभी के लिए 4जी और 5जी वायस-वीडियो काल, संदेश, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 एम6 को अत्यधिक भार ले जाने की उसकी क्षमता के कारण 'बाहुबली' नाम भी दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अमेरिका की यात्रा की थी। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में, दोनों नेताओं ने 2025 को अमेरिका-भारत नागर अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक अग्रणी वर्ष करार दिया था।

'अमेरिकी उपग्रह का भारत से प्रक्षेपण सबसे बड़ी उपलब्धि'

अमेरिका में भारत के राजदूत क्वात्रा ने कहा कि भारत द्वारा एक अमेरिकी संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच साझेदारी के लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल है, और यह वर्ष 2025 में द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग के दौरान हासिल हुई सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण दिन है।'

Jansatta Page No-13

मुद्दा | सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा

भारत में कृत्रिम मेधा से नौकरियां जाने का खतरा कम

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि कृत्रिम मेधा (एआइ) के कारण ज्ञान-आधारित नौकरियों के प्रभावित होने का जोखिम पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत में कम है।

कुल कार्यबल में दफ्तर वाली नौकरियों की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (स्टेम) आधारित रोजगारों का वर्चस्व होने के कारण ऐसा है। कृष्णन ने खास बातचीत में कहा कि रोजगार पर एआइ के संभावित प्रभावों को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, भारत के संदर्भ में उन्हें उसी तीव्रता से नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत में दफ्तर वाली नौकरियों का अनुपात पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है, जिससे दिमाग से किए जाने वाले कार्यों पर आधारित नौकरियों पर एआइ से पड़ने वाला जोखिम सीमित रहता है। कृष्णन ने कहा, 'भारत में अन्य नौकरियों की तुलना में दफ्तर वाली नौकरियों की संख्या कम है। इसलिए ज्ञान-आधारित नौकरियों पर एआइ का जोखिम उतना गंभीर नहीं है जितना अन्य देशों में है। इसके अलावा, दफ्तर वाले अधिकांश रोजगार स्टेम क्षेत्र में हैं, जो हमारे लिए अवसर भी पैदा करते हैं।' आइटी सचिव ने कहा कि एआइ ऐसी पहली प्रौद्योगिकी है, जो मुख्य रूप से ज्ञान-आधारित कर्मचारियों और संज्ञानात्मक श्रम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। पहले की औद्योगिक और अन्य क्रांतियों में मशीनों ने मुख्य रूप से शारीरिक श्रम की जगह ली थी, न कि दिमाग से किए जाने वाले कार्यों को प्रतिस्थापित किया था। हालांकि, उन्होंने इस धारणा से असहमति जताई कि एआइ निकट भविष्य में इंसानी कामगारों की जरूरत को पूरी तरह समाप्त कर देगा।

उन्होंने कहा कि एआइ का वास्तविक असर मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने में होगा, ताकि लोग अपने विश्लेषणपरक मानवीय कार्यों को अधिक कुशलता और उत्पादकता के साथ कर सकें। कृष्णन ने कहा, 'मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता है कि हम इतनी जल्दी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, जहां श्रमिकों की जरूरत ही खत्म हो जाए। एआइ मानव क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे सोच-समझकर किए जाने वाले कार्यों में उत्पादकता बढ़ेगी और संसाधनों तक बेहतर पहुंच संभव होगी।'

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि एआइ से गलत या भ्रामक जानकारी मिलना यानी 'हैलुसिनेशन' अब भी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में एआई से तैयार सामग्री की निगरानी की जरूरत लंबे समय तक बनी रहेगी।

कर्मचारियों को प्रभावित करने की क्षमता

आइटी सचिव ने कहा कि एआइ ऐसी पहली प्रौद्योगिकी है, जो मुख्य रूप से ज्ञान-आधारित कर्मचारियों और संज्ञानात्मक श्रम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि पहले की औद्योगिक और अन्य क्रांतियों में मशीनों ने मुख्य रूप से शारीरिक श्रम की जगह ली थी।

Jansatta Page No-12

नया आयकर अधिनियम एक अप्रैल से होगा लागू

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

भारत ने 2025 में अपने कर ढांचे में व्यापक सुधार किया जिसमें माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में भारी कटौती और आयकर छूट शामिल है। अब ध्यान आगामी बजट में सीमा शुल्क में तर्कसंगत सुधार और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर है। अगले वर्ष एक अप्रैल से नया सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा जो छह दशक से अधिक पुराने, वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। साथ ही दो नए कानून, सिगरेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के लिए और पान मसाला पर जीएसटी दरों के अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए सरकार द्वारा तय की गई तिथि से लागू किए जाएंगे।

सरकार द्वारा 2025 में लागू किए गए कर सुधारों का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक वातावरण के बीच मांग को प्रोत्साहित करना था। शुल्क से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण आर्थिक निर्णय लेने पर असर पड़ने से भारत के कर सुधार उपायों ने घरेलू मांग बढ़ाने, उपभोग को प्रोत्साहित करने और वृद्धि का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस साल एक प्रमुख विशेषता सितंबर 22 से लगभग 375 माल एवं सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती रही जिससे सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर कर का बोझ कम हुआ और लंबे समय से जारी उल्टी कर संरचनाओं (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) की चिंताओं का समाधान हुआ।

इसके अलावा चार-स्तरीय जीएसटी ढांचे (5, 12, 18 और 28 फीसद) को दो मुख्य दरों पांच और 18 फीसद में समेटना अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को तार्किक एवं सरल बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना गया।

जीएसटी में किए गए बदलावों का उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और अधिक पूर्वानुमानित बनाना था जिसमें कर की श्रेणियों की संख्या कम करना और मुकदमों को कम करना शामिल था। संग्रह की दृष्टि से, अप्रैल में जीएसटी संग्रह ने रिकार्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए को छुआ और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में इसका औसत 1.9 लाख करोड़ रुपए रहा।

व्यापक दर कटौतियों के कारण जीएसटी राजस्व पर कुछ दबाव बना, साथ ही वृद्धि दर धीमी हुई। भारत में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह नवंबर में साल के निचले स्तर 1.70 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। यह सालाना आधार पर केवल 0.7 फीसद की मामूली वृद्धि दर्शाता है। नवंबर वह पहला महीना था जिसमें 22 सितंबर से प्रभावी जीएसटी दर कटौती का पूरा असर देखा गया।

चार श्रम संहिताएं नए साल से अस्तित्व में लाने की तैयारी

सरकार ने पांच साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद चार श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 2026 में पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगी। ये नियम देश के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। श्रम मंत्रालय ने 2026 में ईपीएफओ 3.0 संस्करण लाने की भी योजना बनाई है, जो कर्मचारियों की भविष्य निधि की तेजी से निकासी सुनिश्चित करेगा एवं कर्मचारियों की पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन निर्धारण तथा कर्मचारियों की जमाकर्ता-संबंधित बीमा योजना 1976 के तहत बीमा दावों को भी सुविधाजनक बनाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2025 वास्तव में भारत के श्रम एवं रोजगार परिवेश के लिए परिवर्तनकारी वर्ष रहा जिसे ऐसे सुधारों ने चिह्नित किया जो श्रमिकों को शासन के केंद्र में रखते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष की एक प्रमुख उपलब्धि 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं का लागू होना रही।

जी-रामजी में महिलाओं की एक-तिहाई हिस्सेदारी

अरविंद शर्मा • जागरण

- अकेली महिलाओं के लिए विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होंगे
- परिवार के पंजीकरण में सभी वयस्क सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे

नई दिल्ली : ग्रामीण भारत में रोजगार, सम्मान और सुरक्षा को एक साथ जोड़ने की मंशा से लाए गए विकसित भारत-जी-रामजी अधिनियम में महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। इस कानून के तहत कुल लाभार्थियों में महिलाओं की कम से कम एक तिहाई हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। यह प्रविधान सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पंजीकरण से लेकर काम आवंटन, पहचान, भुगतान, निगरानी और शिकायत निवारण तक पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से तय किया गया है। यदि इसका ईमानदारी से पालन हुआ तो जी-रामजी ग्रामीण महिलाओं के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार का मजबूत माडल बन सकता है।

अधिनियम के अनुसार ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए जब किसी परिवार का पंजीकरण होगा तो उसके सभी वयस्क सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे। पत्नी, बेटी या परिवार की मुखिया सबका नाम दर्ज करना होगा। उन्हें अलग से आवेदन देने या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजीकरण की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होगी, जिससे अनावश्यक भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अकेली रहने वाली महिलाओं के लिए अधिनियम में विशेष व्यवस्था है। विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को अलग से विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कार्डों के आधार पर उन्हें काम देने में प्राथमिकता मिलेगी। मकसद है कि उन्हें स्थायी आर्थिक सहारा मिल सके। इन विशेष कार्डों की वैधता तीन वर्ष की होगी। कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पीने के पानी, शौचालय, विश्राम स्थल और बच्चों की देखभाल की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। इससे महिलाओं के लिए काम करना सुरक्षित और सुविधाजनक होगा और वे परिवार व रोजगार के बीच बेहतर संतुलन बना सकेंगी। मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया है।

महिला प्रधान परिवारों को भी प्राथमिकता

ग्राम पंचायतों को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने क्षेत्र में रहने वाली ऐसी महिलाओं की पहचान करें, जो अकेली हैं या जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। उन्हें विशेष रोजगार गारंटी कार्ड उपलब्ध कराएं। महिला प्रधान परिवारों को भी प्राथमिकता दी गई है। ऐसे परिवारों को उन कार्यों में आगे रखा जाएगा, जिनसे भविष्य में आय के स्थायी साधन बन सकें। खेत, तालाब, सिंचाई संरचनाएं, भूमि सुधार, आवास और बुनियादी ढांचे से जुड़े काम न केवल तत्काल मजदूरी देंगे, बल्कि लंबे समय तक लाभ पहुंचाने वाली संपत्तियां भी तैयार करेंगे।

Dainik Jagaran Page No-13

भारत जल्द बनेगा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर, करेगा निर्यात : शाह

अभ्युदय मप्र ग्रोथ समिट में दो लाख करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। विदेश में भी इसका निर्यात करेगा। यह इसलिए होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनेक ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाली जा रही है, जिससे देश को ग्लोबल लीडर बनने का मौका मिलेगा। इसी कड़ी में देश ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में धमाकेदार एंट्री की है और तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। शाह ने यह बात गुरुवार को ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में कही।

पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर आयोजित इस आयोजन में शाह ने कहा कि स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कान्क्लेव की शुरुआत नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते गुजरात से की थी। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट में राज्य के कैपिटल के अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। इसी तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सभी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल कान्क्रेंस और निवेश का भूमिपूजन कार्यक्रम करने की शुरुआत की है। अब उद्यमी मध्य प्रदेश में एक रुपया बोकर करोड़ों कमा सकते हैं। इस मौके पर शाह ने मध्य प्रदेश में दो लाख करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि ग्वालियर की भूमि पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जहां की मिट्टी ने बाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम किया। अटलजी ने न केवल देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की बल्कि जीवन पर्यंत देश के स्वराज को सुशासन से आगे ले जाने का काम किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बनकर रह गया था।

ग्वालियर में गुरुवार को आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ में हैं मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। ● नईदुनिया

किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील

रीवा में अमित शाह ने कृषक सम्मेलन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि आज बीपी-शुगर सहित अन्य प्रकार की बीमारियां अनाज में मिश्रित खाद एवं अन्य रासायनिक की देन हैं। बीमारियों से अगर छुटकारा पाना है तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा। देश में 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। मैं स्वयं भी प्राकृतिक खेती से जुड़ चुका हूं। जब बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती होगी तो इसकी ब्रांडिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी चिंता कर ली है।

Dainik Jagaran Page No-13

चरम क्रूरता का उदाहरण केरल की घटना

केरल के पलक्कड़ जिले (वालायर के पास) में 17 दिसंबर 2025 को एक दर्दनाक घटना हुई। स्थानीय लोगों की भीड़ ने छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मजदूर को चोरी के शक में घेर लिया और बांग्लादेशी घुसपैठिया घोषित कर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। केरल में भी ऐसा हो सकता है, इस ख्याल से मैं सकते में हूं। पीड़ित 31 वर्षीय राम नारायण बघेल छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के करही गांव का रहने वाला दलित प्रवासी मजदूर था। वह काम की तलाश में 13 दिसंबर को केरल गया था और निर्माण स्थल पर दिहाड़ी कर रहा था। एक स्थानीय चोरी की घटना के बाद भीड़ ने राम नारायण को संदिग्ध मान लिया। वीडियो फुटेज में हमलावर उसे 'क्या तुम बांग्लादेशी हो?' पूछते और बार-बार 'बांग्लादेशी' कहकर पीटते दिख रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 80 से ज्यादा चोटें मिलीं, पसलियां टूटी हुई थीं और अत्यधिक रक्तस्राव से मौत हुई। डॉक्टरों ने इसे क्रूर मॉब अटैक बताया।

पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम हैं: अनंतन, अनु, सी प्रसाद, सी मुरली और के बिबिन (सभी स्थानीय निवासी हैं)। इन पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। केरल सरकार ने एसआईटी गठित की है और सभी आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बाकी संदिग्धों की तलाश हो रही है। लेकिन मेरा सवाल अनुत्तरित है कि केरल में भी ऐसा कैसे हुआ? यदि केरल भी नष्ट हो चुका है, तो बचा क्या? मैं कई दिनों से इससे संबंधित वीडियो अनेक पोस्ट में देख रहा हूं और घबरा रहा हूं। उस बेवस इंसान का चेहरा और उसे मारने- पीटने की आतुर भीड़ का संवाद मुझे जड़ कर गया है।

शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार

हाल ही बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास की हत्या ने एक बार फिर अनगिनत सुलगते सवाल खड़े कर दिए हैं, मीडिया समूहों और समाचार पत्रों ने इस मुद्दे को काफी महत्व दिया और समाज एक बार फिर गहरी सोच में डूब गया। पिछले वर्षों से भारत और पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की लक्षित हत्याएं हुई हैं, जिनमें कश्मीर, बंगाल मुख्य रूप से शामिल हैं। हर बार सवाल सुलगे, पर जवाब अनसुलझे ही रहे। पहलगाम हो या मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, अल्पसंख्यक हर बार लक्ष्य रहा व अपनी जान गंवाता रहा। अखलाक की हत्या ने देश से लेकर विदेश तक की मीडिया में जगह बनाई और विपक्ष ने जमकर रुदन किया, पर दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद गहरी खामोशी। इस दोहरे मापदंड का अंत आखिर कब होगा?

मनोज पुरुषार्थी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

सांप्रदायिक हिंसा

असुरक्षा के साये में जीने को मजबूर लोग

बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। यह संकट किसी एक घटना या हालिया राजनीतिक बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास में गहराई तक फैली हुई हैं। सच यह है कि भारत विभाजन के बाद से पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षा व भय के साये में जीने को मजबूर रहे हैं।

विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं, खासकर दलित समुदाय की बड़ी आबादी रह गई थी, जिसका एक कारण दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल का जिन्ना और मुस्लिम लीग का समर्थन था, जिन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि नए देश में दलितों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन जिन्ना की मृत्यु के बाद हालात तेजी से बदले। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े और अंततः मंडल को इस्तीफा देकर भारत लौटना पड़ा, जबकि उनकी बातों पर भरोसा कर वहीं रुके लाखों हिंदू खुद को ठगा हुआ महसूस करते रहे। बांग्लादेश बनने के बाद भी कट्टरपंथी ताकतें समय-समय पर हिंसा, लूट व हत्या के जरिये उन्हें डराती रही हैं।

उधर, दीपू चंद्र दास की हत्या न केवल अमानवीय है, बल्कि यह बांग्लादेश में हिंदुओं की भयावह असुरक्षा का प्रतीक भी है। बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, जान-माल की क्षति की तत्काल भरपाई करने, संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र जांच कराने की मांग करने और विस्थापित होकर भारत आने वाले हिंदुओं को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत शरण देने की आवश्यकता है। साथ ही, सीमा पर कड़े इंतजाम भी जरूरी हैं।

सुभाष खुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

अगर दुनिया में किसी भी भारतवंशी या भारतीय व्यक्ति/समूह के साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार या अत्याचार होता है, तो भारतवासियों को आवाज उठानी चाहिए, ताकि वहां की सरकारों पर दबाव बढ़े और अत्याचार खत्म होकर वहां शांति स्थापित हो सके। वर्तमान परिस्थिति में विपक्षी सांसद या कोई भी सदस्य सस्ती व अव्यावहारिक राजनीति करने से परहेज करे। इस समय पड़ोस में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा सलूक हो रहा है। अतः यह समय ऊल-जुलूल बयानबाजी का नहीं, सही कदम उठाने हेतु सत्ता के साथ सहयोग करने का है। याद रहे, पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलकर नफरत फैला सकता है और चीन भी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकता है। ऐसे में, हमें बहुत सोच-समझकर सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात देशहित में ही कहनी चाहिए।

शकुंतला नेनावा, टिप्पणीकार

Hindustan Page No-10

नए साल में टेक्सटाइल क्षेत्र को मिलेगी नई ऊंचाई

सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता, सात देशों के साथ एफटीए से निर्यात के लिए तैयार होगा बड़ा बाजार

राजीव कुमार ● जागरण

- नई श्रम संहिता के अमल से रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं, बढ़ेगा उत्पादन
- बैंक से मिलने वाले लोन की ब्याज दर में 1.5% की कमी आई, कर्ज मिलना हुआ आसान

नई दिल्ली : टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े उद्यमियों का मानना है कि पिछले कुछ सालों के प्रयास की बदौलत नया साल टेक्सटाइल का साल होगा। उनका मानना है कि काटन जैसे कच्चे माल की सस्ते दाम पर उपलब्धता, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम के तहत उत्पादन विस्तार का मौका, श्रम संहिता में बदलाव, कम ब्याज पर लोन की सुविधा और सात देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से टेक्सटाइल के निर्यात के लिए बड़ा बाजार तैयार होने जा रहा है।

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर कहते हैं, 'नए साल में ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ होने वाले व्यापार समझौते पर अमल शुरू हो जाएगा। अगले साल यूरोपीय यूनियन से भी व्यापार समझौता हो जाएगा। इन देशों के बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश, टर्की जैसे देशों से है। व्यापार समझौते से यह प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। अगले साल से नई श्रम संहिता के पूरी तरह से अमल में आने से रात की शिफ्ट में महिलाएं काम कर सकेंगी, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।' इन सबके अलावा मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य भी टेक्सटाइल उद्यमियों को अलग से कई इंसेंटिव दे रहे हैं। इन सबकी मदद से नए साल में टेक्सटाइल सेक्टर में एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। उद्यमियों ने बताया कि पिछले एक-डेढ़ साल में बैंक से मिलने वाले लोन की ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत की कमी आई है। क्रेडिट गारंटी स्कीम की वजह से लोन मिलना आसान हो गया है। कई राज्य टेक्सटाइल के लिए अलग सब्सिडी दे रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि सिर्फ अगला साल ही नहीं, पूरा दशक टेक्सटाइल का हो सकता है।

> मौजूदा अनुकूल माहौल से अगले सात साल में टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात दोगुना हो सकता है। अप्रामी जनवरी-फरवरी तक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की उम्मीद है और उसके बाद गारमेंट व मेड-अप्स जैसे आइटम के निर्यात को नई ऊंचाई मिल सकती है।
>
> **-संजय जैन,** पूर्व प्रेसिडेंट, कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज

एक दशक में टेक्सटाइल सेक्टर के निर्यात में नहीं हुई कोई वृद्धि

वित्त वर्ष 2014-15 में टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात 41 अरब डालर का था, जो गत वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 38 अरब डालर रह गया। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े गारमेंट का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 17 अरब डालर था जो गत वित्त वर्ष 2024-25 में 16 अरब डालर रहा। टेक्सटाइल सेक्टर में काटन, यार्न, फैब्रिक और गारमेंट शामिल होता है। देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले इस सेक्टर में पिछले 10 सालों में विभिन्न कारणों से कोई तेजी नहीं दिखी जबकि देश का कुल निर्यात 2014-15 में 314 अरब डालर से बढ़कर 2024-25 में 440 अरब डालर तक पहुंच गया।

Dainik Jagaran Page No-11

जू में 17 वर्षों बाद जेब्रा का जन्म, मुख्यमंत्री ने नाम समृद्धि रखा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यहां 17 वर्षों बाद जन्मे जेब्रा शिशु को देखा और उसका नाम समृद्धि रखा। उन्होंने कहा कि जेब्रा के बच्चे का जन्म राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वन्य जीवों की देखभाल अच्छे ढंग से करें। उनकी सुविधाओं का ठीक से ख्याल रखें। भ्रमण के दौरान संजय गांधी जैविक उद्यान में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और मुस्कराते हुए उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों तथा पक्षियों को देखा और उनके स्वास्थ्य-सुविधाओं, कार्यकलापों तथा पर्यावरण संरक्षण की जानकारी ली। संजय गांधी

भ्रमण

- मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों तथा पक्षियों की सुविधाओं की जानकारी ली
- कहा, यहां स्कूली छात्र-छात्राओं का अधिक से अधिक भ्रमण कराएं

जैविक उद्यान में बड़ी संख्या में कराए गए पौधरोपण पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की। यहां भ्रमण करनेवाले बच्चों एवं आगंतुकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहां स्कूली छात्र-छात्राओं का अधिक से अधिक भ्रमण कराएं, ताकि वे वन्य जीवों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। यहां ट्वाय ट्रेन जल्द से जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संजय गांधी जैविक उद्यान के बेहतर विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, उसपर तेजी से कार्य करें।

अधिकारियों के साथ संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ● सौ. आइपीआरडी

सुबह घूमने आने वाले लोगों के लिए बना नया रास्ता

संजय गांधी जैविक उद्यान में सुबह घूमने आने वाले लोगों के लिए नया रास्ता बनाया गया है। गैंडा, घड़ियाल तथा जिराफ के बच्चों के जन्म के समय से ही ध्यान रखने के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की गई हैं। हाल में ही राज्य कैबिनेट से पटना जू के बेहतर प्रबंधन के लिए सोसायटी का भी गठन किया गया है। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डा. चन्द्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एस.एम व संजय गांधी जैविक उद्यान के निदेशक हेमंत पाटिल सहित कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

Dainik Jagaran Page No-5

फल-फूल की खेती को आगे बढ़ाने को बन रहा रोडमैप

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : कृषि भवन के सभागार में गुरुवार को "समृद्ध किसान, सशक्त बिहार- उत्पादन से निर्यात, एकीकृत फल क्रांति" विषयक परिचर्चा का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्ष का एक ऐसा रोडमैप बनाना है, जिससे राज्य में फल एवं उद्यानिकी क्षेत्र को वैज्ञानिक, संगठित एवं बाजारोन्मुख बनाकर किसानों की आय में सतत एवं स्थायी वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि फल एवं उद्यानिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम हो रहा। परिचर्चा में अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच संवाद के माध्यम से फल उत्पादन एवं निर्यात को और अधिक लाभकारी

5 वर्ष के इस रोडमैप का लक्ष्य है किसानों की आय में वृद्धि

बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। फलों के क्लस्टर आधारित माडल को अपनाकर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की प्रतिबद्धता जताई गई। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि किसानों को नवीन तकनीकों, आधुनिक बागवानी पद्धतियों, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मूल्य संवर्द्धन से संबंधित नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इज आफ एग्रीकल्चर से बिहार की खेती को मिल सकती बुलंदी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए कृषि विभाग ने बामेती भवन में राज्य-स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। उद्घाटन कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान के लिए किसान काल सेंटर को सशक्त किया गया है। इज आफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत कम समय में अधिक उत्पादन, बेहतर लाभ, वर्ष में तीन फसलों की खेती और सतत नवाचार के माध्यम से बिहार की कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान विषयक यह संगोष्ठी पटना के साथ राज्य के सभी प्रखंडों में आयोजित हुई। रामकृपाल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार का फसल उत्पाद विश्व के हर कोने तक पहुंचे। बिहार को कृषि के क्षेत्र में अव्वल राज्य बनाना ही हमारा लक्ष्य है। संगोष्ठी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने सहभागिता निभाई। विशेष सचिव डा. वीरेंद्र प्रसाद यादव, कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव, बामेती के निदेशक धनंजय पति त्रिपाठी आदि संगोष्ठी में उपस्थित रहे।

Dainik Jagaran Page No-2

कुछ अलग | बदलाव से भारत की ओर आने वाली हवाओं में कमी आ रही, हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी में गिरावट आई

पिघलता अंटार्कटिका बदल रहा मानसून की चाल

■ शैलेन्द्र सेमवाल

देहरादून। अंटार्कटिका में तेजी से पिघल रही बर्फ भारतीय मानसून की चाल बदल रही है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों के संयुक्त अध्ययन ने यह चेतावनी दी है।

अध्ययन के नतीजों में कहा गया है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानि प्रमुख वर्षा पट्टी दक्षिण की तरफ खिसक रही है। इससे मानसून का पैटर्न प्रभावित हो रहा है। भविष्य में इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। यह अध्ययन नगालैंड की लाइसोंग संरचना से मिली 3.4 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्म पत्तियों पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने करोड़ों वर्ष पहले जैसी जलवायु का निर्माण कर इसका अध्ययन किया। इससे पता चला कि उस दौर में अंटार्कटिका में जमी बर्फ की चादरों ने वर्षा प्रणाली को प्रभावित किया था। भारत के मानसून पर भी इसका असर पड़ा। इसकी वजह थी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ये वह जगह है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हवाएं आपस में मिलती हैं) जो गर्मियों में उत्तर और सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसकता है। इसके उत्तर की ओर खिसकने से भारतीय मानसून की दिशा तय होती है। अभी यह दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इससे भारत की ओर आने वाली हवाओं और दबाव क्षेत्र में कमी आ रही है और मानसून प्रभावित हो रहा है।

हिमालय भी हो रहा प्रभावित

अंटार्कटिका में पिघल रही बर्फ का असर हिमालय पर भी दिख रहा है। कम बर्फबारी, ऊपरी क्षेत्रों में अप्रत्याशित बारिश इन प्रभावों को दर्शाता है। अध्ययन के नतीजे जर्नल पैलियो जियोग्राफी, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, पैलियो इकोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं।

असामान्य बारिश और सूखा बदलते मानसून के संकेत

वर्ष 2024 में पश्चिमी भारत में असामान्य रूप से ज्यादा बारिश और पूर्वोत्तर में सूखे जैसे हालात बदलते मानसून के संकेत हैं। शोध में शामिल वाडिया संस्थान की वैज्ञानिक डॉ. कापेसा लोखो का कहना है कि यह खोज अतीत को समझने से आगे है। यह भविष्य की चेतावनी है। पृथ्वी की जलवायु आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। अंटार्कटिका जैसे दूरस्थ क्षेत्र में बदलाव भारत सहित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की वर्षा प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

Hindustan Page No-15

प्रकृति ने इस साल दुनिया भर में जमकर कोहराम मचाया। भारत से लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश भूस्खलन, बाढ़, आग और चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए। उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई तो पंजाब में बाढ़ से आमजन बेहाल रहे। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से हजारों लोग मारे गए। जलवायु संकट से निपटने की भी कोशिशें हुईं। गुजरते साल के साथ प्रकृति के रौद्र रूप पर एक नजर।

प्रकृति के प्रकोप से दुनिया पस्त

भूस्खलन

उत्तराखंड : मलबा मौत बनकर आया

उत्तरकाशी के धराली में पांच अगस्त को पहाड़ों के बीच से मलबा काल बनकर चला। देखते ही देखते पूरा इलाका मैदान बन गया। कई मकानों और आलीशान होटलों का नामों निशान मिट गया। हादसे में सिर्फ चार लोगों के शव मिले। 52 लापता लोगों में से प्रशासन ने 12 अन्य लोगों को मृत घोषित कर परिवारीजनों को प्रमाण पत्र दे दिया है। तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसे देख लोगों का कलेजा कांप गया। राहत और बचाव कार्य के तहत 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आज भी लोग अपनों की वापसी की आस में हैं।

जम्मू- कश्मीर के किश्तवाड़ में अचानक आए भूस्खलन से मची तबाही।

जम्मू- कश्मीर : मलबे में दबकर 68 की मौत

किश्तवाड़ में 14 अगस्त को आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। मलबे में दबकर 68 लोगों की मौत हो गई जबकि 38 लोग लापता हुए। आपदा के कारण माछिल माता यात्रा मार्ग भी बुरी तरह प्रभावित रहा। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अक्तूबर में बिलासपुर में पहाड़ से अचानक शुरू हुए भूस्खलन की चपेट में एक यात्री बस आ गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी। प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल को कुल करीब 3800 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ।

इंडोनेशिया: 830 लोगों के लिए काल बना पानी

बेतहाशा बारिश के चलते 22 से 25 नवंबर के बीच बाढ़ जैसे हालात बने। इसके बाद अचानक एच, पश्चिमी सुमात्रा और उत्तरी सुमात्रा के क्षेत्रों में भूस्खलन ने भयावह रूप ले लिया। प्रकृति के आक्रोश की चपेट में आकर 830 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब भी 500 लोग लापता हैं। पहाड़ों के टूटने से बड़ी संख्या में मूलभूत ढांचे को क्षति हुई। आठ लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। कुल 30 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसी तरह थाईलैंड में भी भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 185 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।

चक्रवात : हवा से तबाही

एरिन : अठारह दिन तक दिखा असर

अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में आए चक्रवात के दौरान एक मिनट तक 260 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चली। 11 अगस्त से चक्रवात का असर दिखना शुरू हुआ और 28 अगस्त को धीमा पड़ गया। चक्रवात में तीन लोगों की मौत हुई। वहीं अभी भी पांच लोग लापता हैं। तेज हवा से दस लाख डॉलर की क्षति हुई।

मोंथा : चार राज्यों में हालात बिगड़े

चक्रवाती तूफान से अक्तूबर में देश के चार तटीय राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु प्रभावित हुए। अधिकतम 95 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली हवा आठ लोगों की मौत का कारण बनी। वहीं 76 करोड़ डॉलर की संपत्ति को नुकसान हुआ। मोंथा का असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी दिखा और इन राज्यों में हल्की बारिश हुई।

सेन्यार : तीन देशों पर दिखा असर

नवंबर में आए चक्रवात ने 75 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तीन देशों को अपनी चपेट में लिया। सबसे अधिक दक्षिणी थाईलैंड, इंडोनेशिया का सुमात्रा और मलेशिया अधिक प्रभावित रहा। तूफान से थाईलैंड में सबसे अधिक 297 मौतें हुई थी। करीब 1300 लोग मारे गए। 19.8 अरब डॉलर की संपत्ति को नुकसान हुआ।

आग : दुनियाभर में खूब धधके जंगल

भारत : बढ़ती जा रही जंगलों की आग

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस साल जून तक वनों में आग की 2,38,309 घटनाएं हुईं। पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा 34,765 अधिक रहा। मध्य प्रदेश में वनों में आग की सबसे अधिक 97 घटनाएं हुईं। जम्मू- कश्मीर में 94, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में 23 और महाराष्ट्र में 21 घटनाएं सामने आईं। वनों में आग से 36 फीसदी वन क्षेत्र प्रभावित हुआ।

देश के वनों में आग की घटनाएं

2025	2,38,309
2024	2,03,544
2023	2,23,333

अमेरिका : हॉलीवुड हस्तियों की कोठियां खाक

लॉस एंजिल्स के जंगलों में सात जनवरी को धधकी आग को 160 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली हवा ने और विकराल बना दिया था। जंगलों में 14 स्थानों पर लगी आग से पूरा शहर प्रभावित हुआ। हॉलीवुड हस्तियों की आलीशान कोठियां खाक हो गईं। 400 लोग मारे गए। 18 हजार घर और मूलभूत ढांचे आग में स्वाहा हो गए। दो लाख लोगों को कैंप में रहना पड़ा।

ब्रिटेन : वनों की आग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

ब्रिटेन के जंगलों में इस साल धधकी आग से 17 अगस्त तक 47,879 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया। वर्ष 2019 में कुल 47 हजार हेक्टेयर जंगल जले थे। यूरोपियन फॉरेस्ट फायर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार 28 जून को स्कॉटलैंड के दावा क्षेत्र के वनों में आग से 12 हजार हेक्टेयर में फैला जंगल जलकर राख हो गया।

बाढ़ : जनजीवन बेहाल

पंजाब : जलमग्न हो गए खेत और खलिहान

बारिश और बाढ़ ने पंजाब को बुरी तरह प्रभावित किया। 20 अगस्त को पंजाब के 13 जिलों के 1400 गांव जलमग्न हो गए। चार दशक बाद ऐसे हालात दिखे। बाढ़ और बारिश के पानी से कुल 3.71 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। साढ़े तीन लाख लोगों का जन जीवन प्रभावित हुआ। 29 लोगों की मौत हुई।

असम : फसल पूरी तरह खराब

मानसून सीजन के दौरान हमेशा की तरह असम बाढ़ से बेहाल रहा। एक अनुमान के अनुसार बाढ़ के चलते 5.15 लाख लोगों का जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं 12,160 हेक्टेयर फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। बाढ़ में एक हजार से अधिक जानवर बहकर मारे गए। जबकि 4.60 लाख जानवर बुरी तरह प्रभावित हुए। बीस से अधिक लोग बाढ़ के चलते मारे गए।

फिलीपींस : सब तहस नहस

फिलीपींस में 12 दिन की बाढ़ में सब तहस नहस हो गया। 15 से 26 जुलाई के बीच बाढ़ का पानी 30 लोगों की मौत की वजह बना। सड़कों के साथ नॉर्थ लुजॉन एक्सप्रेसवे बुरी तरह प्रभावित हुआ। लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ जबकि एक हजार से अधिक घर टूट गए।

भूकंप ने दहलाया

म्यांमार में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य।

- तिब्बत के टिंगरी काउंटी में सात जनवरी को 7.1 तीव्रता का भूकंप, 400 मौतें
- म्यांमार-थाईलैंड में 28 मार्च को 80 सेकंड तक 7.9 तीव्रता का भूकंप, 5456 की मौत
- दुनिया का सबसे शक्तिशाली 8.8 तीव्रता का भूकंप 2011 में रूस के कमचटका में आया था
- अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 31 अगस्त को 6 तीव्रता का भूंकप, 2217 मौतें
- अनुमान के अनुसार दुनियाभर में इस साल भूकंप के 1791 झटके महसूस हुए

प्राकृतिक आपदा का कहर

220 अरब डॉलर का नुकसान हुआ दुनिया को इस वर्ष

40 अरब डॉलर की क्षति लॉस एंजलिस में आग से हुई

50 अरब डॉलर की क्षति 13 चक्रवातों से दुनिया को

2.5 अरब डॉलर की क्षति जमैका, हैती क्यूबा को चक्रवात से

5,000 हजार से अधिक लोग म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से मारे गए

स्रोत : (स्विस रे इंस्टीट्यूट- 2025)

भारत पेश कर रहा मिसाल

- पवन और सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में भारत चौथे स्थान पर
- करीब 24 लाख घर पीएम सूर्य घर योजना से लैस हुए हैं
- जीवाश्म ईंधन से कार्बन उत्सर्जन 1.4 फीसदी की गिरावट
- कचरे के निस्तारण की दर 16 फीसदी से बढ़कर 81 फीसदी
- देश में इस साल चीतों की कुल संख्या 30 से 33 के करीब है

स्रोत : (पीआईबी, संयुक्त राष्ट्र)

हीट वेव ने सताया

- देश में अप्रैल से जून तक पारा सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा
- अप्रैल से सितंबर तक पूरा यूरोप हीटवेव की लहरों से परेशान रहा
- यूरोपीय देशों में हीट वेव के चलते चार हजार से अधिक मौतें हुईं
- इटली के 27 में से 16 शहरो में रेड हीट अलर्ट जारी किया गया
- तुर्किये में पारा 50.5 डिग्री तो जापान में 41.8 डिग्री तक पहुंचा

सुधार की राह पर...

हरित ऊर्जा : स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन दोगुना होगा

दुनिया के 80 फीसदी देशों में हरित ऊर्जा को बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2030 तक हरित ऊर्जा की क्षमता मौजूदा समय से दोगुना करीब 4600 मेगावॉट हो जाएगी।

महासागर : दशकों की मेहनत अब रंग लाएगी

दुनियाभर में सिर्फ एक फीसदी महासागरीय क्षेत्र सुरक्षित हैं। दशकों तक चली बातचीत के बाद सितंबर 2025 में 30% क्षेत्र को सुरक्षित करने पर सहमति बनी है। मरीन संरक्षित क्षेत्र के तहत कुल 11 लाख स्कवॉयर किलोमीटर क्षेत्र को सुरक्षित किया जाएगा।

जंगल : अमेजन के जंगल में पर्यावरण बैठक

अमेजन के जंगल में कॉप-30 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया को वनों को बचाने का संदेश देना था। संयुक्त कोशिशों का ही नतीजा है कि अमेजन के जंगल में बीते 12 महीनों में पेड़ों की कटाई 11 फीसदी तक घटी है।

वन्यजीव : दुनिया के बाघों का घर बन गया भारत

वन जीवों को बचाने में पूरी दुनिया जुटी है। भारत में बीते एक दशक में बाघों की संख्या दोगुनी होकर 3600 हो गई है। इसी के साथ भारत दुनिया के 75 फीसदी बाघों का घर बन गया है। फ्लोरिडा में पहली बार समुद्र में कछुओं की संख्या में इजाफा देखा गया है।

जलवायु तबाही का सिलसिला अभी तो थमता नहीं दिखता

विशेषज्ञ की राय

हरजीत सिंह
जलवायु विशेषज्ञ, सतत संपदा क्लाईमेट फाउंडेशन

पिछले कई वर्षों से जिस तरह से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है, वह नए साल में भी थमता नहीं दिख रहा। मौजूदा साल के भी गर्म रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस साल वैश्विक तापमान बढ़ोतरी 1.4 डिग्री को पार कर जाएगी।

तापमान में बढ़ोतरी का मतलब यह हुआ कि तबाहियों का जो मंजर साल भर रहा है, वह नए साल में और भयावह हो सकता है, क्योंकि उत्सर्जन में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही। संयुक्त राष्ट्र की हालिया एमिसन गैप रिपोर्ट को देखें तो दुनिया के पास जलवायु खतरों से निपटने के लिए जो संसाधन हैं वह जरूरत से 12-15 गुना तक कम हैं। मौजूदा समय में इन खतरों से निपटने के लिए सालाना 25 अरब डालर खर्च हो रहा जबकि जरूरत 300-350 अरब डालर की है। ऐसे में नए साल में जलवायु वार्ताओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत होगी।

साफ हवा-पानी की उम्मीद : नए साल में यह उम्मीद है कि दुनिया इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के विचार को अमल में लाएगी। अदालत ने कहा था कि नागरिकों को साफ हवा पानी एवं पर्यावरण देना सरकारों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकारों पर दबाव रहेगा कि वे इस दिशा में कार्य करें।

भारत कर रहा अच्छी पहल : भारत तमाम चुनौतियों के बावजूद इस दिशा में अच्छी पहल कर रहा है तथा उसने 50 फीसदी ऊर्जा क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर ली है। परमाणु ऊर्जा और हाईड्रोजन क्षेत्र में निरंतर नए प्रयोग कर रहा।

उम्मीदें@2026

- हरित ऊर्जा और उत्सर्जन घटाने के मुद्दे पर 26 मार्च को बर्लिन में बैठक
- मलेशिया में 30 मार्च को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेंट चेंज पर चर्चा
- वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेंट चेंज सम्मेलन 9 से 10 मई को दुबई में
- पांच जून को अजरबैजान में विश्व पर्यावरण दिवस पर जुटेंगे दिग्गज
- तुर्किये में नौ से 20 नवंबर तक कॉप-31 सम्मेलन में पर्यावरण पर मंथन

सुविधा | कोरोना के बाद बदल रहे बीमारियों के स्वरूप से पार पाने में जुटा स्वास्थ्य विभाग, 5462 बेड का होगा पीएमसीएच, पहले चरण में 1117 बेड का सीएम कर चुके हैं उद्घाटन

विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के अत्याधुनिक भवन में इलाज शुरू

अलविदा 2025

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के अस्पतालों में इस वर्ष सुविधाएं बढ़ी हैं। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के अत्याधुनिक भवन में इलाज शुरू हुआ। आईजीआईएमएस के नए भवन में गंभीर बीमारियों और क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में आधुनिक मशीनों से उपचार शुरू हुआ। पीएचसी और सीएचसी में जांच और दवाइयों की उपलब्धता भी बढ़ी। हालांकि, कोरोना के बाद बढ़ी स्वास्थ्य चुनौतियों से पार पाना अभी बाकी है। कोरोना के बाद बीमारियों के बदलते स्वरूप का ठोस इलाज तलाशने में चिकित्सक जुटे हैं। पीएमसीएच के नए भवन का उद्घाटन 3 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। दो टावर वाले इस भवन की क्षमता 1117 बेड की है, यहां आधुनिक सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। 65 ऑटोमेटेड आईसीयू बेड, 44 पोस्ट आईसीयू बेड, 100 निजी रूम, दस डीलक्स रूम और दो एक्सक्लूसिव सुइट्स के अलावा अत्याधुनिक दस ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड हैं। यहां 160 करोड़ के अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। 2026 के अंत तक अन्य भवन के तैयार होने के बाद अस्पताल की क्षमता 5462 बेड की हो जाएगी। 5545 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 2021 में इसका निर्माण शुरू करने के साथ ही विश्वस्तरीय सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा था, जो 2025 से मिलनी शुरू हो गई हैं। गंभीर मरीजों को लाने-ले जाने के लिए इसकी छत पर हेलीकॉप्टर भी उतराने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के 13856 अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। बिहार पिछले पंद्रह महीने से मुफ्त दवा देने के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है।

पीएमसीएच।

03 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन

पहली मंजिल तक जा रही एंबुलेंस

पीएमसीएच के नए भवन में ओपीडी, इनडोर, ओटी के बाद मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। 22 दिसंबर 2025 से पहली मंजिल तक एंबुलेंस से ही मरीज पहुंच रहे हैं। परिजनों के लिए लिफ्ट सुविधा भी है। नए भवन में ईएनटी विभाग की इनडोर सेवाओं को भी विस्तार दिया गया है। नए मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मियों की तैनाती की जा रही है।

आईजीआईएमएस : 3000 बेड का निर्माण शुरू

पीएमसीएच के विस्तार के साथ ही राज्य के पांच पुराने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पटना स्थित आईजीआईएमएस को तीन हजार की क्षमता का बनाया जा रहा है, जिसपर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईजीआईएमएस में 500 बेड के नए अस्पताल भवन का उद्घाटन फरवरी, 2025 को किया। इस नए भवन में आधुनिक सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी की सुविधा है। आईजीआईएमएस के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में अत्याधुनिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मशीन, मॉड्यूलर ओटी मशीन समेत चार प्रमुख सुविधाओं की शुरुआत अगस्त, 2025 में हुई। इसी प्रकार भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को भी 2500-2500 बेड का बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं से निपटना बड़ी चुनौती

एक तरफ प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और शहरीकरण के बाद नई स्वास्थ्य चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कोरोना के बाद बीमारियों का स्वरूप बदलना भी चिकित्सकों के लिए अबूझ पहेली बनती जा रही है। इन सभी समस्याओं से निपटना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। प्रदूषण के बाद विशेष कर सांस की बीमारियां अधिक बढ़ी हैं। कोरोना के बाद कम उम्र के लोगों में हृदय संबंधी रोग के अधिक मामले पहले की अपेक्षा आने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे बड़ी चुनौती माना है।

Hindustan Page No-2

बिहार के दलों को मिला अधिक चंदा, जदयू और लोजपा आगे

चुनाव आयोग

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य के सभी राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा मिला। संस्थान और आमलोगों ने बड़े दलों को चंदा देने में ज्यादा रुचि दिखाई। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में बिहार से संबंधित राजनीतिक दलों को अधिक चंदा मिला। इसमें जदयू को 1.81 करोड़ की तुलना में 18.69 करोड़ चंदा मिले। लोजपा (रा) को 11.67 लाख की तुलना में 11.09 करोड़ रुपये, भाकपा माले को 43 लाख की तुलना में 49 लाख रुपये चंदा मिला। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, राजद ने अबतक वर्ष 2024-25 में चुनावी चंदे का ब्योरा दाखिल नहीं किया है। जबकि, एआईएमआईएम को वर्ष 2023 - 24 में 9 लाख रुपये चुनावी चंदा हासिल हुआ था जबकि 2024-25 में उसे किसी ने चंदा नहीं दिया।

2024-25 में आय की बिहार के प्रमुख दलों ने जानकारी दी

18.69 करोड़ जदयू को तो लोजपा (रा) को 11.09 करोड़ रुपये मिला चंदा

किसको कितना चंदा

दल	2023-24	2024-25
भाजपा	3967	6654
कांग्रेस	1129	522.13
जदयू	1.81	18.69
लोजपा (रा.)	0.1167	11.09
भाकपा माले	0.43	0.49
एआईएमआईएम	0.09	00
राजद	अनुपलब्ध	

(नोट : राशि करोड़ रुपये में।)

जदयू को सर्वाधिक चंदा इलेक्टोरेल ट्रस्ट से मिला

चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार, जदयू को सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट से हासिल हुआ। प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 10 करोड़, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 5 करोड़ और समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट एसोसिएशन से 2 करोड़ रुपए दिए हैं। 2024-25 में पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट, कंपनियों और व्यक्तियों समेत कुल 66 संस्थाओं से 18.69 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं, लोजपा (रा) को सबसे ज्यादा 10 करोड़ रुपये का चंदा प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला है, जबकि एक करोड़ रुपये प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दिए हैं। पार्टी सांसदों के अलावा निजी कंपनियों व व्यक्तिगत रूप से पार्टी को चंदा उपलब्ध कराया गया है। चुनाव आयोग की मानें तो भाकपा माले को साल 2023-24 में 43 लाख 579 रुपए का चंदा हासिल हुआ था। जो साल 2024-25 में 6 लाख 95 हजार 186 रुपए अधिक है। पार्टी को ज्यादातर विधायक और पूर्व विधायक ने ही चंदा दान किया है। भाकपा माले को वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर,पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) से चंदा हासिल हुआ। भाजपा को पिछले वित्तीय वर्ष में 3 हजार 967 करोड़ रुपये चंदा के तौर पर मिला था जबकि 2024-25 में चंदे के रूप में 6 हजार 654 करोड़ रुपए मिले। जबकि, कांग्रेस को पूर्व में 522.13 करोड़ रुपये मिले थे।

6654 करोड़ रुपये चंदा वर्ष 2024-25 में मिला भाजपा को

राष्ट्रीय दलों में भाजपा को मिलने वाली चंदे की रकम में भारी बढ़ोतरी हुई है जबकि कांग्रेस को मिलने वाली चंदे की रकम में भारी कमी आई है। भाजपा को 2023-24 में 3967 करोड़ रुपये चंदा के रूप में हासिल हुआ था जबकि 2024-25 में चंदे की रकम बढ़कर 6654 करोड़ रुपये हो गई।

Hindustan Page No-2

Useful For Mains

भारत-रूस संबंधों के नए आयाम

पिछले कुछ समय से दुनिया में शक्ति-संतुलन बदल रहा है। ऐसे में भारत-रूस के बीच शीर्ष-स्तरीय संवाद केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संकेत है कि दोनों देश अपनी सामरिक साझेदारी को नई ऊर्जा देना चाहते हैं।

धीरज यादव

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा ऐसे समय में हुई, जब वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ समय से दुनिया में शक्ति-संतुलन बदल रहा है और विभिन्न देशों की विदेश नीतियों में नई प्राथमिकताएं आकार ले रही हैं। ऐसे में भारत और रूस के बीच शीर्ष-स्तरीय संवाद केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यह संकेत है कि दोनों देश वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी अपनी सामरिक साझेदारी को नई ऊर्जा देना चाहते हैं। पुतिन की यह यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलित और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस यात्रा का महत्त्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि विश्व स्तर पर यूक्रेन युद्ध, रूस और पश्चिम देशों के बीच तनाव, रूस-चीन नजदीकी और अमेरिका की नई व्यापार नीतियां मिलकर एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण बना रही हैं। भारत, जो आज वैश्विक दक्षिण की प्रमुख आवाज बनकर उभरा है, ऐसी स्थिति में अपनी विदेश नीति में परिपक्वता और संतुलन दोनों का परिचय दे रहा है। पुतिन की यात्रा का सार यही रहा कि भारत किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेता है।

भारत और रूस के संबंधों की नींव शीत युद्ध काल में पड़ी थी। वर्ष 1971 की भारत-सोवियत मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच ऐसे विश्वास का निर्माण किया, जिसे समय और सत्ता परिवर्तन भी कमजोर नहीं कर सके। रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और विज्ञान-तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत होता गया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आकार देने में रूसी वैज्ञानिक सहयोग निर्णायक रहा। रक्षा क्षेत्र में भी द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हुआ है। भारतीय सेना के लगभग 60-70 फीसद उपकरण किसी न किसी रूप में रूसी तकनीक पर आधारित हैं। एसयू-30 एमकेआइ लड़ाकू विमान, टी-90 टैंक, एस-400 मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस जैसी संयुक्त परियोजनाएं इस विश्वास का प्रमाण हैं। यही ऐतिहासिक संबंध आज भी दोनों देशों को एक-दूसरे की सुरक्षा और रणनीतिक प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील बनाए रखते हैं।

यूक्रेन युद्ध ने यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की भू-राजनीति को बदल दिया है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर नए सहयोगियों की तलाश के लिए प्रेरित किया। एशिया, विशेषकर भारत और चीन, रूस की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरे। भारत ने यूक्रेन संकट पर शुरुआत से संतुलित रुख अपनाया और न तो युद्ध का समर्थन किया, न ही किसी पक्ष का कठोर विरोध, बल्कि संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। यह नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत-रूस संवाद की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के प्रभाव में निर्णय नहीं लेता, बल्कि अपने दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देता है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने इस अवधि में रूस से व्यापक स्तर पर तेल खरीदा, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को महंगाई और आपूर्ति संकट से बचाने में मदद की।

हाल के वर्षों में रूस-चीन संबंधों में भी काफी प्रगाढ़ता आई है। यह

निकटता पश्चिमी प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनावों का स्वाभाविक परिणाम है, मगर इसके भारत पर कई प्रभाव हैं। चीन, भारत का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है और रूस का महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भी बन गया है। यह स्थिति पहली दृष्टि में भारत के लिए चुनौती बन सकती है, हालांकि इसके भीतर अवसर भी निहित है। भारत के लिए रूस सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोगी है। रूस के वैज्ञानिक, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ दशकों से बने भरोसे को केवल चीन की निकटता कम नहीं कर सकती। इस जटिल त्रिकोणीय परिदृश्य में भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक अवसर हैं, जिनके माध्यम से वह रूस के साथ अपने संबंधों को चीन-रूस समीकरण से अलग दिशा में आगे बढ़ा सकता है। इसी संतुलनकारी भूमिका ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

> हाल के वर्षों में रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। यह पश्चिमी प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनावों का स्वाभाविक परिणाम है, मगर भारत पर इसके प्रभाव को लेकर गौर करना जरूरी है। चीन, भारत का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है और रूस का महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भी बन गया है। यह स्थिति पहली दृष्टि में भारत के लिए चुनौती बन सकती है, हालांकि इसके भीतर अवसर भी निहित है। भारत के लिए रूस सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोगी है। रूस के वैज्ञानिक, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ दशकों से बने भरोसे को केवल चीन की निकटता कम नहीं कर सकती।

अमेरिका की ओर से चीन पर शुल्क बढ़ाने के बाद वैश्विक आपूर्ति शृंखला का पुनर्गठन तेज हो गया है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत सहित एशिया के अन्य देशों में वैकल्पिक विनिर्माण क्षमता तलाश रही हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, पर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों के साथ भारत संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति पर चलता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है, जबकि रूस इस क्षेत्र में चीन के साथ गहरी साझेदारी चाहता है। इस विरोधाभासी परिदृश्य में भारत की कूटनीति को अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। भारत ने अभी तक इस संतुलन को कुशलता से निभाया है और यही उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो भविष्य की दिशा संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण के माडल पर आधारित होगी। भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की ओर बढ़ रहा है और रूस इसके लिए एक विश्वसनीय साझेदार बन सकता है। ब्रह्मोस जैसी सफल परियोजनाएं दोनों देशों की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। व्यापार के क्षेत्र में 'नार्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कारिडोर' भारत के लिए यूरोप और मध्य एशिया से जुड़ने का नया मार्ग खोल सकता है। इसके अलावा, यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चल रही बातचीत भविष्य में भारत के व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती है। वैश्विक व्यवस्था तेजी से बहुध्रुवीय स्वरूप ले रही है। अमेरिका, चीन, रूस और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच शक्ति का पुनर्संतुलन बन रहा है। भारत-रूस संबंध इस व्यापक वैश्विक भूमिका के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

आने वाले वर्षों में भारत और रूस ऊर्जा, रक्षा, उर्वरक, आर्कटिक सहयोग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपने सहयोग को नई दिशाओं में विस्तार दे सकते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच तेज आपूर्ति शृंखला विकसित करने में भारत की भूमिका भविष्य में महत्त्वपूर्ण हो सकती है। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लिए रूस उर्वरक का एक स्थिर और किफायती स्रोत बना हुआ है, जिसने वैश्विक मूल्य-वृद्धि के दौर में भारतीय किसानों को बड़ी राहत दी है। रूस की ऊर्जा परियोजनाओं में भारत की भागीदारी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में नई गहराई जोड़ सकती है। साइबर सुरक्षा और नवोन्मेषी डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में रूस की विशेषज्ञता और भारत की तकनीकी क्षमता मिलकर महत्त्वपूर्ण वैश्विक खतरों से निपटने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी संभावनाएं व्यापक हैं, विशेष रूप से गगनयान मिशन और भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं में रूस की भूमिका अहम है। इन सभी आयामों के बीच भारत-रूस संबंधों की स्थिरता इस बात को रेखांकित करती है कि यह साझेदारी केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय होती वैश्विक व्यवस्था में भारत की रणनीतिक आवश्यकता है। मौजूदा परिस्थितियां यही संकेत देती हैं कि दोनों देशों की साझेदारी आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत, बहुआयामी तथा भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विकसित होगी।

माओवाद से मिलती मुक्ति

माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान को फिर से एक बड़ी सफलता मिली। इस बार यह सफलता मिली ओडिशा के कंधमाल जिले में, जहां 1.1 करोड़ के इनामी माओवादी सरगना गणेश उइके अपने चार साथियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इसके कुछ घंटे पहले ओडिशा में ही दो और माओवादी मारे गए थे। ओडिशा में माओवादी सरगना गणेश के मारे जाने के बाद यह राज्य भी माओवाद से मुक्त होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। इसी के साथ देश के अगले वर्ष मार्च तक माओवाद से मुक्त होने के आसार बढ़ गए हैं। इसे गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरह नए सिरे से दोहराया, उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर उनकी प्रतिबद्धता का ही पता चलता है। कितना अच्छा होता कि ऐसी ही प्रतिबद्धता मनमोहन सरकार ने भी दिखाई होती। हालांकि मनमोहन सरकार के समय जब चिदंबरम गृहमंत्री थे तो माओवादियों के खिलाफ आपरेशन ग्रीनहंट चलाया गया, लेकिन उसका विरोध कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ही शुरू कर दिया। इसके चलते यह आपरेशन धीरे-धीरे निष्प्रभावी हो गया। इसकी देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इससे माओवादियों का दुस्साहस बढ़ा। उन्होंने अपने को संगठित कर सुरक्षा बलों पर घातक हमले किए और आदिवासियों का दमन करने के साथ ही विकास कार्यों को रोका और अपनी लूट-खसोट तेज की। इसमें कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए कि माओवाद विषैली विचारधारा से लैस ऐसे हथियारबंद लोगों का निर्मम समूह है, जो गरीबों की हित रक्षा की आड़ लेकर हर तरह की मनमानी और उगाही करता है। हाल के समय में जिस तरह एक के बाद एक माओवादी सरगना मारे गए हैं और बड़ी संख्या में उनके सहयोगियों ने समर्पण किया है, उससे माओवाद अंतिम सांसें लेता हुआ दिख रहा है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि अब माओवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 11 ही रह गई है। एक समय में ऐसे जिलों की संख्या 182 थी। बीते कुछ समय में माओवाद से कई ऐसे क्षेत्र भी मुक्त हुए हैं, जो कभी उनके गढ़ हुआ करते थे। हालांकि कई भूमिगत माओवादी नेता इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वे हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वे हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि माओवादी जब-तब सुरक्षा बलों को चुनौती देते रहते हैं। इसे देखते हुए बचे-खुचे माओवादियों के खिलाफ सख्ती का परिचय देने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें न तो सिर उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए और न ही संगठित होने का। ऐसे हालात पैदा करने होंगे, जिससे उनके सामने समर्पण करने के अलावा और कोई उपाय ही न रहे। भूमिगत माओवादी नेताओं के साथ-साथ उन्हें वैचारिक खुराक देने वाले उन तत्वों पर भी कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए, जो अर्बन नक्सल कहे जाते हैं।

Dainik Jagaran Page No-8

खौफनाक नारेबाजी पर सख्ती जरूरी

संध्या जैन

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि इससे लोगों को कानून को चुनौती देने और दूसरों के प्रति हिंसा एवं उन्हें चोट पहुंचाने का लाइसेंस मिल जाता है

देश में समय-समय पर राजद्रोह कानून को लेकर चर्चा होती रहती है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राजद्रोह कानून का प्रयोग ऐसे उकसावे वाली नारेबाजी के मामले में किया गया, जो अंततः राज्य की सत्ता को चुनौती देते हैं। इसी संदर्भ में बीते दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण कुमार यादव का एक निर्णय चर्चा के केंद्र में है। न्यायमूर्ति यादव ने 'गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा' जैसे नारे को लेकर कहा कि यह लोगों को हिंसक विद्रोह के लिए भड़काने की मंशा से जुड़ा है, जो भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती देता है, इसलिए इस पर राजद्रोह का आरोप लगाना उचित ही है।

यह मामला बरेली में इस साल 26 सितंबर की एक घटना से जुड़ा हुआ है। आल इंडिया इत्तेफाक मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौसीफ रजा ने उस दिन जुमे की नमाज के बाद शहर के इस्लामिया इंटर कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें मुस्लिम युवाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों और झूठे मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने आयोजकों को सूचित किया कि इस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। प्रशासन के इस हस्तक्षेप से उत्तेजित भीड़ ने पत्थरबाजी, फायरिंग से लेकर पेट्रोल बम तक फेंकने शुरू कर दिए। उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस दौरान उत्तेजित भीड़ 'गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा' का नारा भी लगाती रही। काउंसिल के नेता नदीम खान ने भी प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद इस्लामिया इंटर कालेज की ओर कूच करने के लिए लोगों को उकसाया। लगभग पांच सौ लोग उनके घर पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें इस्लाम के नबी के अपमान से जुड़ा विवादास्पद नारा भी शामिल था।

सार्वजनिक व्यवस्था में गतिरोध पैदा करने के लिए नागरिकों को उकसाना राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को खतरे में डालता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का यह अर्थ नहीं कि इससे लोगों को कानून को चुनौती देने और दूसरों के प्रति हिंसा एवं उन्हें गंभीर चोट पहुंचाने का लाइसेंस मिल जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ऐसी नारेबाजी के आरोपितों से स्पष्ट होता है कि भारतीय कानून एवं व्यवस्था के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि यदि किसी धर्म, पंथ या मजहब के

अवधेश राजपूत

आराध्य का अपमान होता है तो यह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 और अन्य धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है। जबकि किसी भी धर्म या ईश्वर के प्रति निंदात्मक कृत्य (ब्लासफेमी) बीएनएस की धारा 299 और 196 के तहत दंडनीय अपराध है। बीएनएस का अध्याय 16 बहुत व्यापक स्वरूप लिए हुए है और इसमें धर्म-पंथ से संबंधित लगभग सभी अपराधों का समावेश किया गया है। जैसे किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से उपासना-स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना (धारा 298), किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने वाले सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण कृत्य (धारा 299) एवं किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर कुछ अपमानजनक शब्दों का उच्चारण आदि (धारा 302) प्रमुख हैं। धर्म या धार्मिक प्रतीकों के विरुद्ध इन अपराधों के लिए विभिन्न धाराओं के तहत तीन से पांच वर्ष तक के कारावास का प्रविधान किया गया है।

'गुस्ताख-ए-नबी...' के नारे की बात की जाए तो यह नबी के अपमान पर ऐसा करने वाले का सिर काटने का आह्वान करता है। सबको पता है कि अभी बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ? यह नारा भारत और भारतीय कानूनी प्रणाली की संप्रभुता एवं अखंडता को चुनौती देता है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को जाति, धर्म या पंथ के बावजूद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य-अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति लोगों को ऐसी सजा देने के लिए उकसाने का प्रयास करता है, जिसका आपराधिक कानूनों में कोई उल्लेख ही नहीं तो स्पष्ट रूप से वह अवैध है। उकसावे की ऐसी कोई भी कवायद या आह्वान बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध है।

देखा जाए तो 'गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा...' का कोई आधार कुरान या हदीस में नहीं मिलता है। इसकी जड़ें तो पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून से जुड़ी हुई मिलती हैं। पाकिस्तान में एक ईसाई महिला आसिया बीबी को 2011 में ईशनिंदा कानून में दोषी ठहराया गया था। पाकिस्तानी पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर ने इसका विरोध किया तो उसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। उस समय मुल्ला खादिम हुसैन रिजवी की अगुआई में इकट्ठा हुई भीड़ ने पहली बार यह नारा लगाया, जो बाद में भारत सहित अन्य तमाम देशों में फैलता गया। अन्य धर्मों के लोगों को डराने, हिंसक विद्रोह के लिए उकसाने तथा राज्य की सत्ता को चुनौती देने के लिए इस नारे के दुरुपयोग की निंदा करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 17 दिसंबर को अभियुक्तों को जमानत देने से इन्कार कर दिया।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार्य नहीं हो सकती। याद रहे कि भड़काऊ, कपटपूर्ण और उकसाने वाली बातों पर प्रतिबंध ही सभ्यता की आधारशिला है। ऐसे प्रतिबंध नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अनिवार्य हैं और राष्ट्रीय संप्रभुता की नींव भी इन्हीं पर टिकी होती है। भारतीय संविधान सभा ने प्रारंभ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की पाबंदी को अस्वीकार किया था, क्योंकि यह स्वराज की मांग का मूल तत्व माना जाता था। हालांकि शीघ्र ही सदस्यों ने सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं की दूरदृष्टि को समझा, जो असीमित वाक्-स्वातंत्र्य पर यथोचित नियंत्रण के पक्षधर थे। अंततः जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रथम संशोधन के माध्यम से राजद्रोह को पुनः कानून में शामिल किया।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

अल्पसंख्यक की परिभाषा तय की जाए

अब जब जनगणना शुरू होने जा रही है, तब इस पर भी विचार होना चाहिए कि भारत में वास्तविक अल्पसंख्यक कौन है? क्योंकि सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण का दुखद नतीजा मातृभूमि के बंटवारे में देखा जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अवश्य है, पर उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने का अधिकार अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत केंद्र सरकार को है। अभी छह समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा पारसी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। इनमें यहूदी नहीं हैं। इस प्रकार अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मानदंड क्या है, यह भी अस्पष्ट है। अल्पसंख्यक समुदायों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इनमें धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक के साथ-साथ आर्थिक सुविधाएं भी शामिल हैं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में न तो शिक्षा का अधिकार कानून लागू है और न ही आरक्षण के नियम। कई ऐसे राज्य भी हैं, जहां कुछ समुदाय राज्य स्तर पर बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ लेते हैं। यदि लाभ वास्तविक वंचित वर्गों तक न पहुंचकर सामाजिक या क्षेत्रीय रूप से मजबूत समुदायों तक पहुंचते हैं, तो इससे अन्य जरूरतमंद वर्गों के अवसर प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ता है और अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को बल मिलता है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश में विभिन्न धर्मावलंबियों की जनसंख्या इस प्रकार थी-हिंदू 79.8 प्रतिशत, मुसलमान 14.2, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4 तथा पारसी 0.006 प्रतिशत। लोकतंत्र में जनसंख्या के बल पर सरकार की नीतियों को प्रभावित किया जा सकता है और किया भी जाता है। अपनी संख्या के बल पर मुस्लिम एक समर्थ तथा प्रभावशाली समुदाय है। यह सरकार को झुक जाने को मजबूर करने में सक्षम है, यह हम शाहबानो मामले में देख चुके हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारण वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि जिन राज्यों में मुस्लिम बहुमत

भीम सिंह

अल्पसंख्यक दर्जे का उद्देश्य सुरक्षा और अवसर प्रदान करना होना चाहिए, न कि स्थायी विशेषाधिकार

अस्पष्ट है अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मानदंड ● प्रतीकात्मक

में हैं, जैसे लक्षद्वीप (96.58) और जम्मू-कश्मीर (68.31 प्रतिशत) वहां भी उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ दिया जाता है। इनके अलावा छह ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है-असम (34.22 प्रतिशत), बंगाल (27.01), केरल (26.56), उत्तर प्रदेश (19.26), बिहार (16.9) और झारखंड (14.53 प्रतिशत)। क्या बड़ी आबादी वाले राज्यों में भी मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए?

अगर जिलों की बात करें तो बिहार में ऐसे 11 जिले हैं, जहां मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। किशनगंज में 67.98, कटिहार में 44.47, अररिया में 42.95 और पूर्णिया में 38.46 प्रतिशत है। यूपी में 15 ऐसे जिले हैं, जहां मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। मुरादाबाद और रामपुर में उनकी आबादी क्रमशः 50.80 तथा 50.57 प्रतिशत है। बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), बलरामपुर, बरेली, मेरठ तथा बहराइच जैसे जिलों में उनकी आबादी 30 प्रतिशत से ज्यादा है। अगर बंगाल की बात करें तो यहां 13 ऐसे जिले हैं, जहां मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद तथा मालदा में वे बहुमत में हैं। यहां उनकी आबादी क्रमशः 66.27 तथा 51.27 प्रतिशत है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल जैसी स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी है। झारखंड के छह जिलों में उनकी आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। असम में वे 11 जिलों में बहुमत में हैं। क्या सघन आबादी वाले जिलों में भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए? अगर हम ईसाई जनसंख्या देखें तो उनकी आबादी तीन राज्यों में बहुमत और पांच अन्य राज्यों में सघन है। कुल 14 ऐसे राज्य हैं, जहां उनकी आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।

जब किसी राज्य की अल्पसंख्यक आबादी यह अनुभव करती है कि बहुसंख्यक होते हुए भी कुछ समुदाय विशेष रियायतें प्राप्त कर रहे हैं तो इससे सामाजिक असंतोष और असमानता की भावना उत्पन्न होती है। अल्पसंख्यक दर्जे का उद्देश्य सुरक्षा और अवसर प्रदान करना होना चाहिए, न कि स्थायी विशेषाधिकार। यदि यह धारणा बनती है कि मजहबी पहचान के आधार पर लाभ मिल रहा है, न कि वास्तविक पिछड़ेपन के आधार पर, तो इससे सामाजिक समरसता और समान नागरिकता की भावना कमजोर पड़ती है। आवश्यक है कि अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। योजनाओं का आधार पंथ के बजाय सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। भारत की एकता उसकी विविधता में निहित है, परंतु नीति-निर्माण में न्याय, संतुलन और पारदर्शिता अनिवार्य है। अल्पसंख्यक संरक्षण के साथ यह भी जरूरी है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग वास्तविक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हो। संतुलित दृष्टिकोण ही राजकोषीय अनुशासन, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण जिला न सही, कम से कम राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए और यदि राष्ट्रीय स्तर पर ही करना हो तो जिस समुदाय की आबादी दो या इससे कम प्रतिशत में हो, उसे ही अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाए।

(लेखक राज्यसभा के सदस्य हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

अपनी जिंदगी के उतार-चढ़ाव से ही लीजिए सबक

यहां स्कैन करें

अनुराग बेहर | सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

मेरे दादाजी सारंगढ़ (छत्तीसगढ़) में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। आजादी के समय सारंगढ़ देश की 600 रियासतों में से एक बहुत छोटी व कम हैसियत वाली रियासत थी। वह आजाद रहना चाहती थी। भारत में सह-अस्तित्व की शर्तों पर शामिल होने की बातचीत के लिए इसके राजा ने दिल्ली में अपना तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजा था, जिसमें एक प्रतिनिधि मेरे दादा भी थे। उस प्रतिनिधिमंडल ने अपने बारे में जो भ्रम पाल रखा था, दादाजी अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए यह कहानी हमें सुनाया करते।

दिल्ली पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल का सारा भ्रम उस समय तिरोहित हो गया, जब उन्हें 14 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। सरदार पटेल तो छोड़िए, उनके सेक्रेटरी ने भी इससे मुलाकात नहीं की। बाद में त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, और जम्मू-कश्मीर जैसी रियासतों को छोड़ तमाम रजवाड़े बिना किसी हील-हुज्जत के भारत में मिल गए। सारंगढ़ को भी मिलना ही था। आखिर 35 किलोमीटर चौड़ी व 40 किलोमीटर लंबी कोई रियासत भारत के बीचोबीच आजाद रहने का तसव्वुर भी कैसे कर सकती थी? साल 2005 में दादाजी का देहांत हो गया। जब वह 14 दिनों तक दिल्ली में थे, तब रोजाना 60 बीड़ी पी जाते थे। वह 'चेन स्मोकर' थे। बाद में 1950 में एक दिन उन्होंने मेरे पिता को, जो तब 11 साल के थे, बीड़ी लाने भेजा। पिता दो लकड़ियों से बीड़ी का बंडल पकड़े हुए लौटे, तो दादाजी ने पूछा, वह ऐसे क्यों बंडल को पकड़े हुए हैं? पिता ने जवाब दिया, 'बीड़ी गंदी चीज है'। तब दादाजी ने कहा, 'अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है, तो ठीक है। मुझे मुट्ठी भर पुदीना ला दे'। पुदीना लेकर उन्होंने बंडल को फेंक दिया और उसके बाद जब भी उन्हें बीड़ी की तलब होती, वह एक पुदीना मुंह में डाल लेते।

जब मैं बड़ा हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं ट्रैफिक निहारना समझता था, उसे दादाजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव के रूप में देखते थे।

सन् 1977 में वह हमारे पास दिल्ली आए। उन दिनों वह सारंगढ़ में वकालत करते थे। हर सुबह वह 10 बजे भोजन के बाद मोती बाग ट्रैफिक सिग्नल के पास फुटपाथ पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते और घंटों ट्रैफिक, पैदल चलने वालों और खोमचे वालों को देखते रहते। एक-दो बार मैं भी उनके साथ गया, पर बोर होकर भाग आया। जब मैं बड़ा हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं ट्रैफिक समझता था, उसे तो वह जिंदगी के उतार-चढ़ाव के रूप में देखते थे।

वह सातवीं में फेल हो गए थे और उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। 1930 के दशक की शुरुआत तक वह जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। उस समय एक मुर्गी चोर ने गरीबी का हवाला देकर उनसे अपना केस लड़ने का अनुरोध किया। दादा वकील नहीं थे, फिर भी उसका केस लड़ा और जीत गए। 1940 के दशक की शुरुआत तक वह सारंगढ़ कोर्ट में सबसे भरोसेमंद वकील बन गए थे। उनमें काबिलियत के साथ कानून का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्वाध्याय से कानून और भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। यह उनकी वकालत की काबिलियत ही रही होगी, जिसने राजा को उन्हें सरदार पटेल जैसे वकील से बातचीत के लिए भेजने को प्रेरित किया।

1950 के दशक की शुरुआत में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें वकालत का विशेष लाइसेंस दिया, क्योंकि उनके पास कानून की डिग्री नहीं थी। वह 95 साल तक जीवित रहे। जीवन के आखिरी दिनों में जब मेरे दादा सारंगढ़ कोर्ट में प्रवेश करते, तो जज भी खड़े हो जाते थे। कई बार हम भोपाल में चार इमली की ढलान पर अगल-बगल चल रहे होते, तो वह अचानक मेरे सामने मुड़ जाते और शंकराचार्य-माधवाचार्य के बीच का दार्शनिक अंतर समझाने लगते।

उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत से लेकर 1990 के दशक में घर में फोन लगने तक मुझे हर दिन एक पोस्टकार्ड लिखा। 25 वर्षों तक हर दिन एक लाइन लिखा पोस्टकार्ड बिना नागा मेरे पास आता रहा। अफसोस, मेरे पास उनमें से एक भी पोस्टकार्ड नहीं है। उनके जीवन ने यह बात मेरे अंदर बिठा दी कि 'जब तक हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं, तब तक कोई भी समय, जगह या हैसियत हमें सार्थक जीवन जीने से नहीं रोक सकती।'

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बड़ी ताकतों की जोर-आजमाइश का साल

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन

सिंहावलोकन- 2025

ट्रंप, टैरिफ और युद्ध के चलते दुनिया में जारी उथल-पुथल के निकट भविष्य में थमने की उम्मीद नहीं है, लिहाजा भारत को घरेलू क्षमता-निर्माण पर ध्यान देना चाहिए।

इस साल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिले, जिनसे शीत युद्ध के बाद के 'एकध्रुवीय दौर' का अंत होता लग रहा है। अमेरिकी वर्चस्व का युग खत्म हो रहा है और यह बड़ी ताकतों के बीच जबर्दस्त मुकाबले व बढ़ती बहु-ध्रुवीयता के कारण संभव हो सका है। हालांकि, अमेरिका के पास अब भी महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं, लेकिन बदल रही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में वैश्विक नतीजों को तय करने की उसकी ताकत तेजी से घटती जा रही है।

'ट्रंप 2.0' की शुरुआत इस साल की संभवतः सबसे बड़ी खबर रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यभार साल की शुरुआत में संभाला और वर्षांत होते-होते यह साफ हो गया कि उनके शासन ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' अब महज बयान नहीं, बल्कि व्यावहारिक हकीकत बन चुका है। उनका प्रशासन शीत युद्ध के बाद की आम सहमति वाली व्यवस्था को नकारकर विकसित हुआ है, जिससे अमेरिका के मित्र और विरोधी, दोनों तरह के देशों के सामने रणनीतिक अनिश्चितता पैदा हुई है। ट्रंप ने 'भार बांटने' के बजाय 'भार सौंपने' की नीति अपनाई और नाटो सहयोगियों से यह वायदा लेने में सफलता हासिल की कि 2035 तक वे अपनी जीडीपी का पांच प्रतिशत रक्षा पर खर्च करेंगे। ट्रंप की 2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यूरोप के 'देशभक्त' (अति-दक्षिणपंथी) दलों से रिश्ते बढ़ाने की बात कहती है, जिसकी कीमत मुख्यधारा के लोकतांत्रिक नेता चुकाते हैं।

इस साल अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ का भार डाला। सहयोगियों व प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ टैरिफ का यह दुरुपयोग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर रहा है, पर साथ ही इसने भारत जैसे मध्यम क्षमता वाले देशों को अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' का दावा करने को भी प्रेरित किया। ऐसा नहीं है कि महज अमेरिका के पीछे हटने से विश्व व्यवस्था नया आकार ले रही है, बल्कि एक सुचिंतित पुनर्संतुलन के साथ-साथ चीन की तकनीकी क्षमता और आक्रामक सक्रियता के कारण भी यह सब हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ऐसी ताकत बन गया है, जो अपने अनुकूल वैश्विक व्यवस्था बनाना चाहता है, जबकि उसकी शर्तें पूर्व में खुद उसी ने गढ़ी है।

साल 2025 में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में आई तेजी है। ऐसा ट्रंप प्रशासन द्वारा यूक्रेन और यूरोप को यह साफ करने के बाद हुआ कि युद्ध को लेकर उसका धैर्य अब जवाब दे रहा है। इस बाबत अगस्त में अलास्का में ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई, लेकिन इससे कोई अंतिम शांति समझौता नहीं निकल सका। रूस लगातार यूक्रेन के विसैन्यीकरण, यानी उसकी सैन्य क्षमता को कम करने पर जोर दे रहा है, जबकि कीव पक्की सुरक्षा गारंटी चाहता है। ट्रंप प्रशासन 20 सूत्री शांति योजना को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें एक 'स्थिर' सीमा रेखा और विसैन्यीकृत बफर क्षेत्र का सुझाव दिया गया है। युद्ध के मैदान में भारी नुकसान झेलने के कारण रूसी सेना धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। माना जाता है कि इस जंग में अब तक उसके 11 से 12 लाख सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं, जिनमें से चार लाख तो इसी साल हताहत हुए। वहीं, यूक्रेन को 46,000 से अधिक जवानों का नुकसान हुआ है और लाखों लोग घायल हुए हैं।

हाल-फिलहाल परमाणु हथियारों का मुद्दा भी वैश्विक चेतना में फिर से उभरा। रूस द्वारा अपनी परमाणु नीति में संशोधन करने और अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के एलान के साथ ही 'तीसरे परमाणु युग' की शुरुआत हुई। ट्रंप ने मई 2025 में चार कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत किए, जिनका मकसद 2050 तक अमेरिकी परमाणु ऊर्जा क्षमता को चार गुना तक बढ़ाना और परमाणु नियामक आयोग में सुधार करना था। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, चीन के पास अब परमाणु हथियारों की संख्या 600 हो चुकी है, जो 2024 में करीब 500 थी। इतना ही नहीं, लगता यही है कि वह 'लॉन्च ऑफ वार्निंग' नीति अपना चुका है, जिसमें दुश्मन की तरफ से महज चेतावनी मिलते ही परमाणु मिसाइल दागे जा सकते हैं। उधर, वैश्विक प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की समय-सीमा करीब आने के साथ ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक संवेदनशील मसला बना हुआ है।

दक्षिण एशिया की बात करें, तो 2025 में यहां तब तनाव पसर गया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव शुरू हो गए। दरअसल, 22 अप्रैल को भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाकर पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, जिसके जवाब में भारत ने पहले सिंधु नदी जल संधि को निलंबित किया और फिर 'ऑपरेशन सिंदूर' की कार्रवाई की। 10 मई, 2025 को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हुई सीधी बातचीत के बाद इस संघर्ष पर विराम लगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। अब नई दिल्ली ने स्थान की परवाह किए बिना आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने का अख्तियार हासिल कर लिया है।

इस बीच, इस क्षेत्र की राजनीतिक तस्वीर में भी बदलाव जारी रहे। श्रीलंका और बांग्लादेश में हम पहले ही देख चुके हैं, तो इस साल नेपाल की बारी थी, जहां 'जेन जेड विद्रोह' ने दशकों से जड़ें जमाई पारंपरिक राजनीतिक सत्ता को उखाड़ फेंका। इसकी शुरुआत 4 सितंबर को हुई, जब केपी शर्मा ओली सरकार ने यू-ट्यूब और वाट्सएप सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। असहमति को दबाने का यह दांव उल्टा पड़ा और 'नेपोकिड्स' अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें नौजवानों ने बेरोजगारी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। इस हिंसक विरोध-प्रदर्शन की परिणति प्रधानमंत्री ओली की विदाई से हुई और पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार का जिम्मा संभाला। इस तरह पहली बार यहां कोई महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इस विद्रोह ने बेशक नेपाल को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसने शासन सुधार की राह भी तैयार की, जिसका नतीजा है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय चुनाव कराने का एलान।

साफ है, यह साल विश्व राजनीति के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा। निकट भविष्य में इसके थमने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा, इससे निपटने के लिए भारत को घरेलू क्षमता-निर्माण पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रश्न : भारत–रूस संबंधों के नए आयामों की चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा : लगभग 400 शब्द |

भूमिका

- शीत युद्ध के बाद बदली वैश्विक शक्ति-संरचना में भारत–रूस संबंधों ने नए संदर्भ और आयाम ग्रहण किए हैं।
- यह संबंध केवल द्विपक्षीय न होकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को संतुलन देने वाला तत्व बन गया है।

---

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं निरंतरता

- सोवियत संघ काल से भारत–रूस संबंध विश्वास, आपसी सम्मान और रणनीतिक सहयोग पर आधारित रहे हैं।
- 1971 की मैत्री संधि ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत किया।
- शीत युद्ध के बाद भी संबंधों में स्थिरता बनी रही।

---

2. राजनीतिक एवं रणनीतिक आयाम

- दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंचों पर सहयोग।
- रूस भारत को एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है।

---

3. रक्षा सहयोग : सबसे मजबूत स्तंभ

- भारत का बड़ा रक्षा आयात रूस से जुड़ा रहा है।
- संयुक्त उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण और दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी।
- रक्षा सहयोग ने भारत की सामरिक क्षमताओं को सुदृढ़ किया है।

---

4. ऊर्जा एवं आर्थिक आयाम

- तेल, गैस और परमाणु ऊर्जा में रूस भारत का प्रमुख साझेदार।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट में रूस से रियायती ऊर्जा आयात भारत के लिए लाभकारी रहा।
- द्विपक्षीय व्यापार को स्थानीय मुद्राओं में बढ़ाने की पहल।

---

5. बदलता वैश्विक परिदृश्य और नई चुनौतियाँ

- रूस–पश्चिम तनाव और चीन–रूस निकटता भारत के लिए संतुलन की चुनौती।
- अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के बावजूद रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना।
- भारत द्वारा 'इश्यू-बेस्ड डिप्लोमेसी' का अनुसरण।

---

6. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष सहयोग

- अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, साइबर और उन्नत प्रौद्योगिकी में सहयोग के नए अवसर।
- मानव संसाधन, शिक्षा और नवाचार में संभावनाएँ।

---

7. भविष्य के नए आयाम

- व्यापार विविधीकरण, फार्मा, कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग।
- आर्कटिक क्षेत्र, समुद्री मार्ग और लॉजिस्टिक्स में साझेदारी।
- रक्षा से आगे व्यापक आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता।

निष्कर्ष

- भारत–रूस संबंध बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन में स्थिरता का आधार हैं।
- यह साझेदारी केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व की अनिवार्य आवश्यकता है।